राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः- प.2(2)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 03 JUN 2019

-::अधिसूचना::-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2/न्याय/3/72 दिनांक 26.06.1973, क्रमांक प.1(3)न्याय/93 दिनांक 29.07.1993 एवं क्रमांक प.1(1)न्याय/91 दिनांक 07.01.1993 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमायें निम्नानुसार पुनः नियत करती है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	जिला	क्षेत्रीय अधिकारिता की पुनरीक्षित सीमाएँ/ क्षेत्राधिकार
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर	अजमेर	पुष्कर पुलिस स्टेशन का क्षेत्र, पुष्कर तहसील का न्यायपालिका क्षेत्र, पीगांसन तहसील (मांगलियावास आरक्षी केन्द्र स्थित गांवों को छोड़कर), पीगांसन पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत् आने वाले समस्त गांव
2.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	अजमेर	नसीराबाद छावनी एवं नसीराबाद शहरी क्षेत्र, नसीराबाद शहर पुलिस स्टेशन का क्षेत्र, नसीराबाद सदर पुलिस स्टेशन का क्षेत्र, आरक्षी केन्द्र मांगलियावास के अन्तर्गत् आने वाले समस्त गांव, नसीराबाद तहसील के अन्तर्गत् आने वाले समस्त गांव (न्यायालय की आर्थिक सीमा तक)
3.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	अजमेर	नसीराबाद छावनी एवं नसीराबाद शहरी क्षेत्र, नसीराबाद शहर पुलिस स्टेशन का क्षेत्र, नसीराबाद सदर पुलिस स्टेशन के ग्राम, आरक्षी केन्द्र मांगलियावास के अन्तर्गत् आने वाले समस्त गांव, नसीराबाद तहसील के अन्तर्गत् आने वाले समस्त गांव (न्यायालय की आर्थिक सीमा तक)

राज्यपाल के आदेश से,

03/6/19

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No.Gen/II/07/07/ 754 Dated:.05../07/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1.All Registrars, Rajasthan High Court Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. District & Sessions Judges , Ajmer.
3.Chief Judicial Magistrate, Ajmer.
4..Concerned Courts.
5.A.O.J.,Confidential/ Statistics/ R.J.S.(Estt.)/ S.C (Estt.)/ Budget/ Building Section and Computer Cell with a direction to upload the same on High Court website.

05.7.19

REGISTRAR (RULES)